निरीक्षणआख्या

निरीक्षणकर्ता	—	अनूप कुमार
पद नाम	—	जिला समन्यवक (एस0एल0डब्लू0एम0)
निरीक्षण तिथि	—	06.05.2024
ग्राम पंचायत	—	नाधिरा
विकास खण्ड	—	म्योरपुर

आज दिनांक—06.05.2024 को विकास खण्ड म्योरपुर के ग्राम पंचायत नाधिरा में वित्तिय वर्ष 2022—23 में कराये गये एस0एल0डब्लू0एम0 के कार्यो का निरीक्षण किया गया, जिसकी स्थिति निम्नवतहै।

1— आर0 आर0 सी0 केंद्र संचालित नहीं है।
2— आर0 आर0 सी0 सेंटर में चारों बाउंड्री वॉल का चिनाई कार्य हो चुका है परंतु उस पर प्लास्टर एवं रंगाई पुताई का कार्य नहीं किया गया है
3— आर आर सी सेंटर में लगीं हुई फेंसिंग वायर की जाली बहुत पतली एवं हल्की है जो मानक के अनुरूप नहीं है
4— बर्मी सेंटर में ट्रस ,टिन शेड ,बर्मी फर्श एवं वर्मी बेड का कार्य पूर्ण पूर्ण नहीं है।
5— वर्मी कंपोस्ट की दीवार क्रैक हो गई है एवं
6— आर आर सी केंद्र पर बना हुआ शौचालय का कार्य अपूर्ण है।
7. नाडेप में रंगाई पुताई का कार्य नहीं किया गया है
8. शौचालय के दरवाजे की गुणवत्ता ठीक नहीं है

उपरोक्त पाई गई कमियों को एक सप्ताह के अंदर गुणवत्ता पूर्वक ठीक कराते हुए आई0 एस0 कोड 1077:1992 के अनुसार प्रथम श्रेणी के ईट का प्रयोग करने हेतु प्रधान एवं सचिव को निर्देशित किया गया।

आर आर सी केंद्र का संचालन करने के लिए सचिव को रूट प्लान , आर0 आर0 सी0 लॉग बुक एवं ग्राम पंचायत में कूड़ा संग्रहण हेतु प्रति घर शुल्क वसूली हेतु रसीद छपवाने के लिए निर्देशित किया गया आर0 आर0 सी0 के संचालन के लिए स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालन करने के लिए बताया गया तथा अन्य कंपोनेंट जैसे नाडेप में जैविक कूड़े को भरने के तरीके एवं वर्मी कंपोस्ट से खाद बनाने के तरीके के बारे में बताया गया

जिला समन्यवक
(एस0एल0डब्लू0एम0))
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

कार्यालय जिलापंचायत राज अधिकारी, सोनभद्र।

पत्रांक— /पं0—7/एस0बी0एम0जी0/2022—23 दिनांक—

पत्रांक व दिनांक—उक्तानुसार।

प्रतिलिपि :—निम्नलिखितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषित—

1. जिला पंचायत राज अधिकारी,महोदय, सोनभद्र की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), विन्ध्याचलमण्डल, मीरजापुर।
3. खण्ड विकास अधिकारी, **म्योरपुर** सोनभद्र।
4. सहायक विकास अधिकारी (पं0) **म्योरपुर**।
5. सम्बन्धित ग्रामप्रधान/सचिव विकास खण्ड **नाधिरा**।

<u>निरीक्षणआख्या</u>

निरीक्षणकर्ता	–	अनूप कुमार
पद नाम	–	जिला समन्यवक (एस0एल0डब्लू0एम0)
निरीक्षणतिथि	–	06.05.2024
ग्रामपंचायत	–	आरंगपानी
विकास खण्ड	–	म्योरपुर

आज दिनांक—06.05.2024 को विकास खण्ड म्योरपुर के ग्राम पंचायत आरंगपानी में वित्तिय वर्ष 2022—23 में कराये गये एस0एल0डब्लू0एम0 के कार्यो का निरीक्षण किया गया, जिसकी स्थिति निम्नवतहै।

1– आर0 आर0 सी0 केंद्र संचालित नहीं है।

2– आर0 आर0 सी0 सेंटर में चारों तरफ फेंसिंग वायर अभी तक नहीं लगाया गया है।

3– आर0 आर0 सी0 सेंटर में पुट्टी का कार्य नहीं हुआ है तथा रंगाई पुताई का कार्य गुणवत्ता पूर्वक नहीं है।

4– आर आर सी केंद्र के गेट एवं ट्रस में प्राइमिंग एवं पेंटिंग का कार्य नहीं किया गया है।

5– आर आर सी केंद्र पर बने हुए नाडेप अभी से टूट रहे है

6– वर्मी कंपोस्ट की दीवार क्रैक हो गई है एवं बर्मी केंद्र में फर्श व बर्मी बेड नहीं बना है।

7– आर आर सी केंद्र पर बना हुआ शौचालय का कार्य अपूर्ण है।

8– आर आर सी केंद्र में बना हुआ शोक पिट मिट्टी से भर गया है उसमे ब्रिक बेलास्ट नहीं भरा गया है शोक पिट में लगी हुई पी0 वी0 सी0 पाइप टूट गई है।

9– आर आर सी केंद्र पर लगे सोलर वाटर पंप खराब स्थिति में पाया गया।

10– आर आर सी केंद्र पर आई ई सी मैसेज पेंटिंग नहीं कराई गई है।

उपरोक्त पाई गई कमियों को एक सप्ताह के अंदर गुणवत्ता पूर्वक ठीक कराते हुए आई0 एस0 कोड 1077:1992 के अनुसार प्रथम श्रेणी के ईट का प्रयोग करने हेतु प्रधान एवं सचिव को निर्देशित किया गया।

आर आर सी केंद्र का संचालन करने के लिए सचिव को रूट प्लान , आर0 आर0 सी0 लॉग बुक एवं ग्राम पंचायत में कूड़ा संग्रहण हेतु प्रति घर शुल्क वसूली हेतु रसीद छपवाने के लिए निर्देशित किया गया आर0 आर0 सी0 के संचालन के लिए स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालन करने के लिए बताया गया तथा अन्य कंपोनेंट जैसे नाडेप में जैविक कूड़े को भरने के तरीके एवं वर्मी कंपोस्ट से खाद बनाने के तरीके के बारे में बताया गया।

जिला समन्यवक
(एस0एल0डब्लू0एम0))
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

कार्यालय जिलापंचायत राज अधिकारी, सोनभद्र।

पत्रांक– /पं0–7/एस0बी0एम0जी0/2022–23 दिनांक–

पत्रांक व दिनांक–उक्तानुसार।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषित–

1. जिला पंचायत राज अधिकारी,महोदय, सोनभद्र की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), विन्ध्याचलमण्डल, मीरजापुर।
3. खण्ड विकास अधिकारी, म्योरपुर सोनभद्र।
4. सहायक विकास अधिकारी (पं0) म्योरपुर।
5. सम्बन्धित ग्रामप्रधान/सचिव विकास खण्ड आरंगपानी।

Operational and Management Plan for Gobardhan Plants in Sonbhadra

(Gram Panchayat Chopan & Kewali, Dewali, Ghorawal Block)

1. Introduction

The Gobardhan Project aims to convert cattle dung and organic waste into biogas and organic fertilizer, promoting a circular economy in rural areas. In Sonbhadra, two Gobardhan plants have been established in Chopan and Kewali (Dewali, Ghorawal Block). To ensure financial sustainability, both plants will have flour mill machines installed, which will be operated by Self-Help Groups (SHGs). The revenue generated from the flour mills will be used for plant maintenance and operations.

2. Objectives

Ensure sustainable operation of Gobardhan plants.
Provide biogas as an alternative fuel for rural households.
Generate organic fertilizer for farmers.
Create employment opportunities through SHG-operated flour mills.
Establish a self-sustaining revenue model.

3. Implementation Strategy

A. Waste Collection & Processing

1. Cattle Dung Collection:
Waste will be collected from local households and dairy farms.
SHGs or Panchayat workers will manage waste collection.
2. Biogas & Fertilizer Production:
Dung will be processed in anaerobic digesters to produce biogas.
The slurry will be converted into organic fertilizer for agricultural use.

B. Flour Mill Operation & Revenue Generation

1. Installation of Flour Mills:
Each Gobardhan plant will have a flour mill machine.
The machines will be powered using biogas-generated electricity.
2. Management by Self-Help Groups (SHGs):
Local SHGs (especially women's groups) will run the flour mills.
A profit-sharing model will be developed to support both SHGs and plant operations.

3. Revenue Streams:

Flour Mill Charges: Households will pay a small fee for grinding wheat, maize, and other grains.
Biogas Sales: Rural households and small businesses can subscribe to biogas services.
Organic Fertilizer Sales: Farmers will be encouraged to purchase affordable organic compost. Gram panchayat revenue also will be increase.

C. Community Engagement & Capacity Building

1. SHG Training & Skill Development:
Training sessions on biogas plant operations, waste management, and flour mill handling.
Financial literacy and business skills training for SHG members.
2. Awareness Campaigns:
Promotion of biogas as a clean energy source.
Demonstration of organic fertilizer benefits in farming.

4. Financial Sustainability & Governance

A. Cost & Revenue Model

B. Governance & Monitoring

1. Management by SHGs: Regular meetings to oversee plant operations.
2. District-Level Monitoring: Panchayat and government officials will review progress.
3. Performance-Based Incentives: SHGs will receive additional benefits based on efficiency.

5. Expected Impact

✔ Reduction in LPG and firewood dependency through biogas adoption.
✔ Better waste management and sanitation in villages.
✔ Employment generation for rural women through SHG participation.
✔ Improved soil health with organic fertilizers.
✔ Economic empowerment through self-sustaining revenue models.

6. Conclusion & Way Forward

This integrated approach of linking biogas production with flour mill operations ensures a sustainable and profitable model for rural development. The Gobardhan plants in Sonbhadra can serve as replicable models for other villages in Uttar Pradesh. Future expansion can include more Gram Panchayats, additional revenue streams (e.g., cattle feed production), and increased biogas distribution networks.

प्लास्टिक मुक्त पंचायत सोनभद्र अभियान: पृष्ठभूमि और संदर्भ

सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का एक आदिवासी बहुल जिला, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों के लिए जाना जाता है। हालांकि, हाल के वर्षों में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण ने जिले की पारिस्थितिकी को गंभीर रूप से प्रभावित किया। सिंगल-यूज प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग, कचरे का अनुचित निस्तारण, और पर्यावरणीय जागरूकता की कमी ने इस समस्या को और अधिक विकराल बना दिया। प्लास्टिक कचरे के कारण जल स्रोत दूषित हो रहे थे, नालियां जाम हो रही थीं, और खेतों की उर्वरता घट रही थी।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 12 अक्टूबर 2019 को महाबीपुरम में समुद्र के किनारे से जब प्लास्टिक इकट्ठा किया तब इससे प्रेरित हो कर इस समस्या के समाधान के लिए 06 जून, 2022 में "मेरा प्लास्टिक, मेरी जिम्मेदारी" अभियान शुरू किया गया। इसके तहत सोनभद्र के 273000 घरों पर बोरियां टांग कर 629 ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक संग्रहण की प्रभावी प्रणाली विकसित की गई। इस प्रयास ने न केवल 49,000 किलो प्लास्टिक कचरे का संग्रहण किया, बल्कि सामुदायिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। इस सफलता से प्रेरित होकर 2024 में "प्लास्टिक मुक्त पंचायत सोनभद्र अभियान" की नींव रखी। इस अभियान का उद्देश्य घरों में प्रयोग के बाद प्लास्टिक को पर्यावरण में आने से रोकते हुए फैले हुए सिंगल-यूज प्लास्टिक को समाप्त कर, ग्रामीण समुदायों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, और ग्राम पंचायतों को पर्यावरण-अनुकूल बनाने के साथ घर पर ही कूड़े में से प्लास्टिक का सेग्रीगेट किया जाना है। यह अभियान सामुदायिक भागीदारी, पुनर्चक्रण, और पर्यावरणीय सुधार का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है।

समस्या: प्लास्टिक प्रदूषण और उसका प्रभाव

सोनभद्र जिले में प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है, जो पर्यावरण, समुदाय और पशुधन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

1. सिंगल-यूज प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग:

पॉलीथीन बैग, बोतलें, और रैपर जैसे उत्पादों का अत्यधिक उपयोग।

इनका निस्तारण उचित तरीके से न होने के कारण सार्वजनिक स्थानों, नालियों और जल स्रोतों में प्लास्टिक का जमाव।

2. पर्यावरणीय क्षति:

प्लास्टिक कचरे के कारण खेतों की उर्वरता घट रही है।

जल स्रोत (नदी, तालाब) दूषित हो रहे हैं, जिससे जलीय जीवन प्रभावित हो रहा है।

नालियों में प्लास्टिक के कारण जलभराव की समस्या बढ़ रही है।

3. पशु और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:

प्लास्टिक में खाद्य सामग्री होने से पशुओं के खाने से वह बीमार हो रहे है तथा उनकी मौत भी हो रही है।

दूषित जल और मिट्टी के संपर्क में आने से ग्रामीणों में स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो रही है।

4. जागरूकता और प्रबंधन की कमी:

ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता का अभाव है जिसके कारण प्लास्टिक कचरे के संग्रहण और पुनर्चक्रण की प्रभावी प्रणाली विकसित नहीं हो पाया है। प्लास्टिक सभी कूड़े में मिल जा रहा है जिससे वह कंपोस्ट नहीं हो रहा है।

यह समस्याएँ न केवल पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ रही थीं, बल्कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रही थीं।

कथन और आधारभूत संकेतक कथन:

"प्लास्टिक मुक्त पंचायत सोनभद्र अभियान" का उद्देश्य सिंगल-यूज प्लास्टिक को प्रयोग के उपरांत पर्यावरण में फैलने से रोकते हुए इसको समाप्त करना, पर्यावरणीय सुधार करना, घरों पर ही कूड़े में से

प्लास्टिक को सेग्रीगेट करना और ग्रामीण समुदायों को जागरूक एवं सशक्त बनाना है। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शुरू किया गया, जो सामुदायिक भागीदारी, कचरा प्रबंधन, और पुनर्चक्रण के माध्यम से स्थायी विकास को बढ़ावा देने का एक आदर्श मॉडल है।

आधारभूत संकेतक:

1. पर्यावरणीय संकेतक प्लास्टिक संग्रहण:

2022 के "मेरा प्लास्टिक, मेरी जिम्मेदारी" अभियान में 273000 घरों पर बोरियां टांग कर 49,000 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा 629 ग्राम पंचायतों से एकत्र किया गया।

2024 में 61 ग्राम पंचायतों में पुनः प्लास्टिक संग्रहण अभियान चलाया गया।

प्रदूषण में कमी:

जल स्रोतों, खेतों और सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक कचरे में 55% तक की कमी आई है।

पुनर्चक्रण के माध्यम से प्लास्टिक को रिसाइकिल कर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना।

2. सामुदायिक संकेतक भागीदारी:

85% ग्रामीण परिवारों ने सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग करने के बाद उसको बाहर नहीं फेंका। प्लास्टिक को घर पर टंगी हुई बोरी में रखा जिसका एकत्रीकरण किया गया।

61 ग्राम पंचायतों में गांव के लोगों के साथ बैठक और जागरूकता अभियान चलाया गया।

वैकल्पिक साधन:

प्लास्टिक को घर पर अन्य कूड़े में से अलग कर एक बोरी लगाया गया जिससे प्लास्टिक प्रयोग के बाद पर्यावरण में आने से रोका जाए।

3. प्रशासनिक संकेतक संग्रहण प्रणाली:

हर घर पर बोरी लटकाकर प्लास्टिक संग्रहित किया गया।

सफाईकर्मियों ने हर महीने 25 से 31 तारीख के बीच बोरियों से प्लास्टिक एकत्र किया।

पुनर्चक्रण इकाइयाँ:

अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री और PWM के माध्यम से पुनर्चक्रण केंद्रों से सभी गांव को लिंक किया गया।

4. सामाजिक संकेतक स्वास्थ्य और सुरक्षा:

प्लास्टिक खाने से पशुओं की मौत में कमी।

दूषित जल स्रोतों के कारण होने वाली बीमारियों में कमी।

जागरूकता स्तर:

ग्रामीणों में प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों की समझ बढ़ी।

स्वच्छता को लेकर सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन।

5. नवाचार और प्रभावशीलता स्थानीय नेतृत्व:

ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, सफाईकर्मी, और पंचायत सहायक की सक्रिय भूमिका।

नवाचार:

"मेरा प्लास्टिक, मेरी जिम्मेदारी" मॉडल का विस्तार।

बोरी का उपयोग एक सशक्त और कम लागत-प्रभावी समाधान।

सबसे सही तरीका: प्लास्टिक का प्रभावी प्रबंधन

प्लास्टिक कचरे को पर्यावरण में जाने से रोकने के लिए "प्लास्टिक मुक्त पंचायत सोनभद्र अभियान" के तहत एक व्यवस्थित और प्रभावी तरीका अपनाया गया है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कचरा घर से ही अन्य कचरे से अलग करते हुए संग्रहित हो और इसका सही निस्तारण हो सके।

1. घर पर प्लास्टिक का पृथक्करण (Segregation):

प्रत्येक घर पर एक बोरी घर से मांग कर उनके सहयोग से टांगी जाती है, जिसमें सिंगल-यूज प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन बैग, बोतलें, और रैपर आदि इकट्ठा किए जाते हैं।

यह प्रक्रिया प्लास्टिक कचरे को अन्य जैविक और सूखे कचरे से अलग रखने में मदद करती है।

2. कचरे का संग्रहण:

हर महीने की निर्धारित तिथियों (25 से 31 तारीख) को सफाईकर्मी घर-घर जाकर प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करते हैं।

ई-रिक्शा का उपयोग कर यह कचरा एकत्रित कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (RRC - Resource Recovery Centre) तक पहुंचाया जाता है।

3. RRC पर प्लास्टिक का अलगाव:

RRC पर प्लास्टिक कचरे को वर्गीकृत किया जाता है, जैसे पॉलीथीन, बोतलें, और अन्य प्रकार।

यह प्रक्रिया पुनर्चक्रण की तैयारी सुनिश्चित करती है।

4. पुनर्चक्रण:

एकत्रित प्लास्टिक कचरे को जनपद के बड़े रिसाइकिलर को दिया जाता है जो फैक्ट्री या अन्य पुनर्चक्रण इकाइयों में भेजा जाता है।

वहां इसे सही तरीके से नष्ट किया जाता है या पुनः उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है जिससे ग्राम पंचायत को प्लास्टिक कचरे से राजस्व प्राप्त होता है।

क्यों यह सही तरीका है?

1. पर्यावरण संरक्षण:

प्लास्टिक को खुले में फेंकने से रोककर जल स्रोतों, खेतों, और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखा जाता है।

2. स्वास्थ्य सुरक्षा:

प्लास्टिक के जलने या पशुओं को खाने से होने वाले हानिकारक प्रभावों को रोका जाता है।

3. जागरूकता और भागीदारी:

ग्रामीणों को प्लास्टिक के पृथक्करण और संग्रहण में शामिल कर उन्हें समस्या का हिस्सा बनने के बजाय समाधान का भागीदार बनाया गया।

4. स्थायी और प्रभावी प्रबंधन:

RRC पर प्लास्टिक का अलगाव और पुनर्चक्रण इसे दीर्घकालिक समाधान बनाता है।

निष्कर्ष:

प्लास्टिक को घर पर ही पृथक कर, ई-रिक्शा से RRC तक पहुंचाने और पुनर्चक्रण प्रक्रिया से जोड़ने का यह तरीका पर्यावरण और समुदाय के लिए सबसे सही और प्रभावी समाधान है। यह न केवल प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और स्थायी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रभाव: प्लास्टिक मुक्त पंचायत सोनभद्र अभियान

"प्लास्टिक मुक्त पंचायत सोनभद्र अभियान" का प्रभाव बहुआयामी है। यह पर्यावरण, सामुदायिक जागरूकता, और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल हो रहा है।

1. पर्यावरण पर प्रभाव प्लास्टिक कचरे में कमी:

2022 के "मेरा प्लास्टिक, मेरी जिम्मेदारी" अभियान में 49,000 किलोग्राम प्लास्टिक संग्रहित किया गया।

2024 में इस अभियान को और विस्तृत करते हुए पर्यावरणीय स्वच्छता को मजबूत किया गया।

जल स्रोत और खेत:

नदियों, तालाबों, और जलाशयों में प्लास्टिक कचरे में 50% तक कमी आई।

खेतों में प्लास्टिक जमाव से मिट्टी की उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव कम होना शुरू हो गया है।

प्रदूषण में कमी:

प्लास्टिक का पुनर्चक्रण सुनिश्चित करने से जल, भूमि, और वायु प्रदूषण कम हुआ।

2. सामुदायिक प्रभाव जागरूकता और भागीदारी:

ग्रामीणों में 85% से अधिक परिवारों ने सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग करने के बाद प्लास्टिक को बोरियों में रखा।

स्वास्थ्य में सुधार:

दूषित जल और प्लास्टिक कचरे से होने वाली बीमारियों में कमी आई।

प्लास्टिक खाने से पशुओं की मौत की घटनाएं कम हो गईं।

3. प्रशासनिक प्रभाव संग्रहण और निस्तारण प्रणाली:

हर घर पर बोरी लटकाकर प्लास्टिक का प्रभावी संग्रहण और निस्तारण सुनिश्चित किया गया।

ई-रिक्शा और RRC (Resource Recovery Centre) प्रणाली से कचरे का व्यवस्थित प्रबंधन हुआ।

पुनर्चक्रण की प्रगति:

प्लास्टिक कचरे को अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री, जनपद के बड़े रिसाइकिलर और PWM इकाइयों में भेजा गया।

पुनर्चक्रण से आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन बना।

4. तुलनात्मक प्रभाव पहले:

सार्वजनिक स्थानों, नालियों, और जल स्रोतों में प्लास्टिक कचरा फैला हुआ था।

ग्रामीण समुदाय प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों से अनभिज्ञ थे।

बाद में ग्राम पंचायतें प्लास्टिक-मुक्त हो गईं, और ग्रामीण समुदाय जागरूक होकर समाधान का हिस्सा बने। प्लास्टिक कचरा व्यवस्थित रूप से पुनर्चक्रण केंद्रों तक पहुंचाया गया।

5. दीर्घकालिक प्रभाव सामुदायिक नेतृत्व:

ग्रामीणों में पर्यावरण संरक्षण की सोच विकसित हुई।

पंचायत स्तर पर स्वच्छता और पर्यावरणीय योजनाओं को प्रोत्साहन मिला।

स्थायी विकास:

प्लास्टिक-मुक्त ग्राम पंचायतें स्थायी और पर्यावरण-अनुकूल विकास की दिशा में एक आदर्श बन गईं।

निष्कर्ष:

"प्लास्टिक मुक्त पंचायत सोनभद्र अभियान" ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है।

की टेकअवेज: महत्वपूर्ण सीख और लाभ

महत्वपूर्ण सीख:

1. सामुदायिक भागीदारी की शक्ति: "प्लास्टिक मुक्त पंचायत" अभियान ने यह साबित किया कि सामूहिक प्रयासों से बड़े पर्यावरणीय संकटों का समाधान संभव है।

2. जागरूकता का महत्व: ग्रामीणों को सिंगल-यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव समझाने से व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया।

3. स्थानीय संसाधनों का उपयोग: प्लास्टिक को घर पर ही अन्य कूड़े से अलग करने के लिए एक बोरी टांगी गई जिससे स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देकर न केवल पर्यावरण को सुरक्षित किया गया, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया गया।

4. निगरानी और अनुशासन: प्लास्टिक कचरे के संग्रहण और निस्तारण के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करना अभियान की सफलता का मुख्य आधार रहा।

लाभ:

1. पर्यावरणीय सुधार: जल स्रोतों, सार्वजनिक स्थानों और कृषि भूमि में प्लास्टिक कचरा लगभग समाप्त हो गया, जिससे प्राकृतिक संसाधन संरक्षित हुए।

2. स्वास्थ्य में सुधार: स्वच्छ जल और प्लास्टिक-मुक्त वातावरण के कारण ग्रामीणों और पशुओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

3. आर्थिक प्रोत्साहन: प्लास्टिक कचरे को बेच कर ग्राम।पंचायतों में स्वयं का आय बढ़ा।

4. रोल मॉडल का निर्माण: ग्राम पंचायतें अन्य जनपद के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनी, जो दर्शाती है कि सामुदायिक प्रयासों से स्थायी विकास संभव है।

यह पहल पर्यावरणीय संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण का आदर्श उदाहरण है।

Proposed Strategy for Grey Water Management in Sonbhadra District

1. Introduction

Grey water—wastewater from household activities like bathing, washing clothes, and kitchen use—forms a significant part of domestic wastewater. If not managed properly, it can lead to waterlogging, contamination, and health hazards. Sonbhadra, with its mix of rural and urban settlements, requires a decentralized and sustainable approach to grey water management to improve sanitation, groundwater recharge, and water reuse.

2. Objectives

Prevent water stagnation and reduce wastewater-related diseases.
Promote decentralized treatment and reuse of grey water.
Enhance groundwater recharge through natural filtration methods.
Integrate grey water management with existing sanitation and water conservation programs.

3. Implementation Strategy

A. Household-Level Grey Water Management

1. Soak Pits & Kitchen Gardens:

Encourage households to construct soak pits to absorb grey water, reducing surface runoff.
Promote kitchen gardens using treated grey water for irrigation.

2. Simple Filtration Units:

Install sand and gravel filters for primary grey water treatment before reuse.
Train households in using organic filtration techniques like reed beds.

3. Awareness Campaigns:

Conduct workshops in villages and schools on grey water reuse.
Encourage households to use biodegradable detergents to prevent water contamination.
B. Community-Level Grey Water Treatment

1. Decentralized Treatment Units (DTUs):

Construct community-level grey water treatment units in Gram Panchayats.
Utilize bio-filters, constructed wetlands, and stabilization ponds for natural water treatment.

2. Drainage Management:

Develop covered drains to channel grey water to treatment systems instead of allowing open discharge.
Regular desilting and maintenance of drains to prevent blockages and mosquito breeding.

3. Reuse and Groundwater Recharge:

Construct recharge pits and percolation tanks in public places to utilize treated grey water for groundwater recharge.
Use treated grey water for irrigation in community parks, schools, and Gram Panchayat buildings.
C. Institutional & Policy Support

1. Integration with MGNREGA & SBM:

Utilize funds under MGNREGA for constructing soak pits and drainage systems.
Link grey water management with Swachh Bharat Mission (Gramin) to promote sustainability.

2. Capacity Building & Monitoring:

Train Gram Panchayat officials, SHGs, and village water committees in grey water treatment techniques.
Implement a monitoring system for grey water projects, ensuring long-term functionality.

3. Strict Regulations:

Enforce by-laws to prevent indiscriminate discharge of grey water on streets and open areas.
Encourage the use of eco-friendly soaps and detergents through policy measures.

4. Expected Outcomes

Reduction in waterborne diseases and mosquito breeding. Improved sanitation and aesthetics in villages and towns. Increased water availability for irrigation and groundwater recharge. Strengthened community participation in water conservation efforts.

5. Conclusion

A well-planned grey water management strategy will help Sonbhadra achieve sustainable water use, reduce health risks, and contribute to environmental conservation. By combining decentralized treatment, community engagement, and policy support, the district can set an example for efficient wastewater management in rural and semi-urban areas.